

# राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा

वर्ष 14 अंक 2

जुलाई-दिसम्बर 2012

1. "ग्रामीण वृद्ध कृषि श्रमिक : मद्यपान और अन्य समस्यायें"—डॉ. हितेश कुमार एन. पटेल, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, (गुजरात)

महात्मा गांधी ने कहा था कि "मद्यपान को मैं चोरी और यहां तक कि वेश्यावृत्ति से भी अधिक भयंकर मानता हूँ। क्या ये दोनों ही बुराइयाँ इससे (मद्यपान) से उत्पन्न नहीं होती हैं।"<sup>1</sup> वास्तव में मद्यपान अनेकानेक समस्याओं की जड़ है। दूसरी ओर वृद्धावस्था के संबंध में बेन्जामिन ने लिखा है कि वृद्धावस्था एक विशिष्ट बीमारी के समान है। यह बीमारी जो प्रत्येक व्यक्ति को लगती है और अन्य सब बीमारियाँ इस बीमारी को निरपवाद रूप से जकड़ लेती हैं।<sup>2</sup> मद्यपान और वृद्धावस्था दोनों यदि समाज के निम्न आर्थिक वर्ग के व्यक्ति अर्थात् कृषि श्रमिक को पकड़ लें तो कल्पना नहीं की जा सकती कि उस व्यक्ति का जीवन कितना समस्याग्रस्त होगा। प्रस्तुत आलेख इसी स्थिति को उजागर करने की दिशा में एक प्रयास कहा जा सकता है।

2. "विस्थापन एवं पुनर्वास का प्रभाव"—डॉ. सी.एस.एस. ठाकुर, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.),

सुप्रिया सिंह, शोध अध्ययत्री, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

राष्ट्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए बड़ें पैमाने पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए खनन कार्य, सड़क एवं बांध का निर्माण अनिवार्य है। इसके कारण अधोसंरचना के विकास के स्थल के मूल निवासियों का विस्थापन अनिवार्य होता है। शासकीय नीतियों के तहत इनका पुनर्वास किया जाता है परन्तु जीवन के विभिन्न आयामों पर इनका सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव लक्षित होता है। प्रस्तुत शोध प्रपत्र कोयला परियोजनाओं के कारण पुनर्वासित समूह के जीवन पर विस्थापन एवं पुनर्वास के विविध आयामों को विश्लेषित करने का एक प्रयास है।

3. "बलात्कार : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण"—प्रोफेसर गोपी रमण प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, के.एस. कॉलेज, लहेरिया सराय (बिहार)

सांप्रत भारत में संपूर्ण देशवासियों के दिलो-दिमाग को जिस गंभीर समस्या ने झकझोर रखा है तथा जो भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से एक कलंक है वह है बलात्कार। इस समस्या की गंभीरता एवं व्यापकता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि देश में 2012 में लगभग 17520 बलात्कार हुए। प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत इस समस्या का समाजशास्त्रीय आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

4. "बौद्ध धर्म में पर्यावरण बोध"—डॉ. आशा कुमारी, इतिहास विभाग, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)

मनुष्य एवं प्रकृति के बीच पूर्ण समन्वय रहा है किन्तु बदलते समय के साथ स्थितियाँ बदल रही हैं। जो प्रकृति सदैव दिल खोलकर अपनी संपदा मनुष्य तथा अन्य जीवों पर लुटाती रही है उससे सबकुछ हड़प लेने के दृःसाहस में मनुष्य ने अपने आपको संकट में डाल लिया है। अपनी सुख-समृद्धि के लिए आज मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने पर उतारू हैं जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। ईसा पूर्व छठी

शताब्दी में जब भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ उस समय भी पर्यावरण की समस्या थी। भगवान बुद्ध ने तब पर्यावरण बोध को अपने धार्मिक दार्शनिक विचारों के माध्यम से व्यक्त किया था। प्रस्तुत आलेख बौद्ध धर्म के अंतर्गत इसी पर्यावरण बोध को उजागर करने का एक प्रयास है।

#### 5. "विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर परिवार के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन"—डॉ० तिर्मल सिंह, बी० एड० विभाग, डी.एस.एन. पी. जी. कालेज, उन्नाव (उ.प्र.)

सांप्रत भारत में ऐसा कहा जाता है कि छोटे अथवा एकल परिवार अपने बच्चों का पालन-पोषण बड़े अथवा संयुक्त परिवारों की तुलना में बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसी सोच के संदर्भ में प्रस्तुत आलेख में छोटे अथवा एकल परिवार तथा बड़े अथवा संयुक्त परिवार के छात्र-छात्राओं की विज्ञान विषय की शैक्षिक उपलब्धि का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

#### 6. "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महिला आन्दोलन"—डॉ० आनन्द कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, टी०एन०बी० कॉलेज, भागलपुर (बिहार)

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख लक्ष्य विदेशी साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाना था। इसके लिए धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकजुटता की भावना पैदा करके एक राष्ट्रीय पहचान विकसित करने की आवश्यकता थी। महिलाओं को दरकिनारा करके यह काम संभव नहीं था। इसलिए महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के साथ-साथ आह्वान किया गया कि वे हर किस्म के अमानवीय शोषण एवं दमन से लड़ने को तैयार रहें। गाँधी जी ने उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन एवं राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ महिला आन्दोलन को बल मिला। प्रस्तुत लेख इसी स्थिति को उजागर करने का एक प्रयास है।

#### 7. "महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता— शिक्षित महिलाओं के संदर्भ में"—डा० मंजू अग्निहोत्री, अस्थायी प्रवक्ता, समाजशास्त्र विभाग, अकबरपुर डिग्री कालेज, अकबरपुर, कानपुर देहात, (उ०प्र०), डा० अंजू रानी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, ए०एन०डी० कालेज, कानपुर (उ०प्र०)

यह एक अजीब विडम्बना है कि आजादी के 65वें साल में जहाँ भारत करीब-करीब हर क्षेत्र में प्रौढ़ता हासिल करने का गौरवपूर्ण जघ्न मना रहा है। उसी के राज्य उत्तर प्रदेश में महिला राजनीतिज्ञ अभी भी शैषव में होने का संताप मना रही हैं। पहली लोकसभा से लेकर 1996 की लोकसभा तक में समग्र भारतीय राजनीति में अनेक गुणात्मक परिवर्तन आये और उनसे नए आयाम भी प्राप्त हुए। इस दौरान लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 499 से बढ़कर 544 तक जा पहुंची। लेकिन महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र से लेकर राजनीति तक बराबर का हिस्सा तथा महत्व देने के तमाम नारों, वायदों और घोषणाओं के बावजूद कठोर सत्य यह है कि उक्त सदन में महिला सांसदों का आंकड़ा 10 प्रतिषत तक भी पहुंच नहीं पाया है। प्रस्तुत अध्ययन शिक्षित महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का आकलन करने का एक प्रयास रहा है।

#### 8. "भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला मानवाधिकार : दशा और दिशा"—डॉ० ज़किया रफ़्त, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, आर०बी०डी० (पी०जी०) कॉलेज, बिजनौर (उ.प्र.)

महिलाओं के मानवाधिकारों को आज विश्व स्तर पर मान्यता दी गयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं व पुरुषों के समान अधिकारों की वकालत की है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर अनेकों ऐसे नियम, कानून, आचार संहितायें हैं जो महिलाओं के मानवाधिकारों के संरक्षण से सम्बन्धित हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने सदैव मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली को अपनाया। भारतीय संविधान के अध्याय तीन में मानवाधिकारों को संरक्षित किया गया है तथा समय-समय पर संशोधन कर उन अधिकारों को परिमार्जित करने की प्रक्रिया भी अपनायी गयी है। प्रस्तुत आलेख भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला मानवाधिकारों की दशा और दिशा का तथ्यपरक एवं तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

**9. "पर्यावरण क्षरण और जनजाति हाशियाकरण"—डॉ. अनिता धुर्वे, वरिष्ठ व्याख्याता, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.), रमेश पाल, शोध अध्येता, समाजशास्त्र, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)**

पर्यावरण क्षरण की बात हम बीसवीं सदी से करते आ रहे हैं। विज्ञान के बढ़ते हुये चरणों ने पर्यावरण क्षरण की समस्या को बढ़ाया है। जहां एक ओर विज्ञान ने मानव जीवन के लिये वरदान साबित हुआ है वहीं मानव के लिये संकट भी पैदा किया है। समाजशास्त्रीय शब्दावली में विज्ञान के प्रकार्य और अकार्य (विशेषतः अप्रकट दुस्कार्य) दोनों ही हैं। औद्योगीकरण व मानव द्वारा उपभोक्तावादी प्रवृत्ति ने पर्यावरण के क्षरण में मुख्य भूमिका निभाई है। प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत पर्यावरण क्षरण के विभिन्न पक्षों तथा वन्यजातीय जीवन पर इसके प्रभावों का उल्लेख किया गया है।

**10. "ग्रामीण नगरीय अन्तर्क्रिया : लखनऊ जनपद के एक गांव का समाजशास्त्रीय अध्ययन"—डॉ. अमूल्य सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, डी.एस.एन. (पी.जी.) कालेज, उन्नाव (उ.प्र.)**

यद्यपि भारत गाँवों के देश के रूप में प्रसिद्ध है जबकि यहाँ नगरीय केन्द्रों की भी प्राचीन परम्परा रही है और इन नगरों तथा इनके पृष्ठ प्रदेशों में बसे गाँवों के बीच परस्पर क्रिया के सुनिश्चित रूप थे, यह सम्पर्क अब कहीं अधिक विकसित है। गाँव अब भी विशिष्टता लिए हुए है बल्कि उसके स्वरूप में परिवर्तन आया है यहाँ नगरीय चिन्ह स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो रहे और गाँव नये रूप में उभर रहा है। प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि सांप्रत भारत में ग्रामीण-नगरीय अन्तःक्रिया के फलस्वरूप गाँव एक नए रूप में उभर रहा है।

**11. "मानव अधिकार और पुलिस प्रशासन — समस्याएं एवं समाधान"—डॉ. श्रीमती साधना पाण्डेय, सहा. प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र, स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय, बैरसिया, भोपाल (म.प्र.)**

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकार किया था। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो मानव के जीवन, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से वे अधिकार जो मानव समाज के विकास के लिए मूलभूत हैं वे मानव को केवल इस आधार पर मिलने चाहिए कि वह मानव है। किसी भी समाज के लोग पुलिस को अपना अर्थात् मानवाधिकारों का संरक्षक मानते हैं किन्तु यदि पुलिस संरक्षक की भूमिका से अलग भूमिका निभाए तो उसे संरक्षक नहीं माना जा सकता क्योंकि इसी स्थिति में मानवाधिकारों का हनन होता है। प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत मानवाधिकारों के संदर्भ में पुलिस की विवादास्पद भूमिका, इससे उत्पन्न समस्याओं तथा सुझावों को प्रस्तुत किया गया है।

**12. "ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकतायें और उनकी पूर्ति में शासकीय योजनाओं का योगदान"—डॉ. संजय खरे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय स्वशासी कन्या उत्कृष्टता स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर (म.प्र.),**

सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकतायें रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति में किसान वर्ग, मजदूर कारीगर, उद्योग घंटों में लगे श्रमिकों की भूमिका अहम है। इनके योगदान के बिना सभ्य एवं सभ्यता जैसे शब्द अर्थहीन हैं। राष्ट्र की मजबूती एवं देश का सर्वांगीण विकास इसी वर्ग पर आधारित है। ये वर्ग अधिकांशतः ग्रामीण जीवन से संबन्धित हैं। अतः ग्रामीण समुदायों का पुनरुत्थान एवं विकास अत्यावश्यक है। जिसके लिए सरकार ने अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हुई हैं। ये शासकीय योजनाएं ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में कितनी सफल हो रही है। प्रस्तुत अध्ययन में यही जानने का प्रयास किया गया है।

**13. "लोक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति छात्र-छात्राओं का दृष्टिकोण"—डा० टी० ए० अशरफी, एसोशिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस० जी० जी० एस० कॉलेज, पटना (बिहार)**

भ्रष्टाचार सम्पूर्ण लोक जीवन से प्रत्यक्षतः संबंधित एक गंभीरतम समस्या है। सामाजिक जीवन के समस्त क्षेत्रों, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आदि को भ्रष्टाचार रूपी दानव ने अपने पाश में जकड़ रखा है। फलतः समस्त राष्ट्र पतन के गर्त की दिशा में अग्रसर है। देश में भ्रष्टाचार के विषाक्त परिवेश के संबंध में हमारी युवा पीढ़ी की सोच क्या है, प्रस्तुत आलेख इसी जानकारी को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास है।

**14. "भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी आंदोलन की भूमिका: एक विश्लेषण"—मनीष महन्त, सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र शासकीय महाविद्यालय, राऊ, इन्दौर (म.प्र.)**

भारतीय राजनीति में विशेषकर राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी आंदोलन की भूमिका का उचित व निष्पक्ष विश्लेषण नहीं हो पाया है। जहाँ लोगों को महात्मा गाँधी, भगतसिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, तिलक जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के बारे में जानकारी है किन्तु वहीं एक भी कम्युनिस्ट नेता के बारे में ठीक से नहीं जानते और न ही उनके राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के बारे में। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में वामपंथी आन्दोलन की भूमिका तथा इसे नरजअंदाज किए जाने के कारणों को प्रकाशित किया गया है।

**15. "स्वामी विवेकानंद: वेदांत-दर्शन"— डॉ. प्रेमलता तिवारी, प्राध्यापक हिन्दी विभाग, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह, जिला-खरगोन (म.प्र.)**

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द का नाम संसार की उन प्रख्यात विभूतियों के बीच गिना जाता है जिन्होंने इस भारत भूमि पर जन्म लेकर सम्पूर्ण विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित कर दिया। वह एक अद्वितीय विद्वान थे, एक ऋषि थे, उनकी वाणी में ओज था, व्यक्तित्व में आकर्षण था, उन्होंने भारत का मान संसार में ऊँचा उठाया था तथा वह राष्ट्रनायक के रूप में पूजे जाते थे। स्वामी विवेकानन्द वेदांत के महान प्रचारक थे। उनके विचार से वेदांत विश्व के समस्त विवादों को सुलझाने का एकमात्र साधन है। वह वेदांत को मानव कल्याण का मूलमंत्र समझते थे। प्रस्तुत आलेख में स्वामी जी के वेदांत-दर्शन को आलोकित करने का प्रयास किया गया है।

**16. "बौद्ध धर्म में महिला-पुरुष समानता : मिथ्या या वास्तविकता"—डा० नन्दन कुमार, इतिहास विभाग, जगदम कॉलेज, छपरा (बिहार)**

प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का उदय भारतीय समाज में परिवर्तनवादी सोच को प्रदर्शित करता है। इस सोच का सम्बन्ध उन समस्त बातों से था जिनसे प्राचीन भारतीय समाज का शोषण हो रहा था। शोषण की इन प्रवृत्तियों को अस्पृश्यता, कर्मकाण्ड, सामाजिक असमानता और स्त्रियों की हीन अवस्था (दुर्दशा) जैसी बातों में देखा जा सकता है। प्रस्तुत आलेख बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और सोच का समीक्षात्मक प्रयास प्रस्तुत करता है।

**17. "सोनभद्र की अनुसूचित जनजातियाँ : मानवशास्त्रीय अध्ययन"—मीताश्री श्रीवास्तव, शोध अध्येत्री, मानव विज्ञान विभाग, इलाहाबाद वि०वि० इलाहाबाद (उ.प्र.), संदीप कुमार, शोध अध्येता, मानव विज्ञान विभाग, इलाहाबाद वि०वि० इलाहाबाद (उ.प्र.)**

भारत विश्व में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला देश है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकानेक ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज तक भी प्रत्येक दृष्टि से सभ्यता के निचले एवं आदिम स्तर पर अवस्थित हैं। ये मानव समूह सभ्य समाज से दूर पहाड़ी, पठारी अथवा जंगली क्षेत्रों में निवासित हैं। इन्हें आदिवासी, आदिम जाति, वन्यजाति, जनजाति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भारतीय संविधान में

इन्हें अनुसूचित जनजाति नाम दिया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जनपद की अनुसूचित जनजातियों का परिचय देना है क्योंकि पूरे प्रदेश में सोनभद्र में ही अधिकांश जनजातीय जनसंख्या निवासरत है।

**18. "दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन"—डा० आरती रावत, समाजशास्त्र विभाग, हे.न.ब. गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर (उत्तराखण्ड)**

दूरदर्शन संचार का एक प्रभावी माध्यम है। दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों के द्वारा समाज में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। दृश्य तथा श्रुत्य माध्यम होने के कारण जनमानस पर इसके कार्यक्रमों का प्रभाव सीधे पड़ता है। दूरदर्शन में दर्शकों को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता है। प्रसारित कार्यक्रम, देखने वाले व्यक्ति को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं इस शोध पत्र के माध्यम से ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

**19. "भारत में नव-बौद्ध आन्दोलन की प्रकृति एवं स्वरूप"—श्रीमती रीमा पाण्डेय, शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र, शासकीय टी०आर०एस० उत्कृष्टता महाविद्यालय, रीवाँ (म.प्र.)**

परम्परागत हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में उच्च स्थान पाने की जटिल प्रक्रिया में निम्न जाति के तीन मार्ग—सामाजिक संघर्ष, संस्कृतिकरण एवं धर्मान्तरण थे। दलितों ने सामाजिक अन्याय से मुक्ति एवं समानता, स्वतंत्रता पर आधारित समाज व्यवस्था के लिये सभी प्रकार के प्रयास किये। दलित आन्दोलनों के कार्यक्रमों के अंतर्गत दलितों ने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये संघर्ष किये। उच्च प्रस्थिति प्राप्ति के लिये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अपनाई। अपेक्षित परिणाम न पाकर धर्म परिवर्तन भी किया। बौद्ध धर्मान्तरण दलित आन्दोलन की दशा में सामने आया। प्रस्तुत लेख भारत में नव-बौद्ध आन्दोलन की प्रकृति एवं स्वरूप द्वैतीयक तथ्यों पर आधारित है।

**20. "स्मृतिकालीन जाति व्यवस्था"—डॉ. अजीत राव, प्राध्यापक इतिहास विभाग, गर्ग डिग्री कालेज, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)**

जाति व्यवस्था भारत की अतिशय जटिल एवं विलक्षण संस्था है इसके संबंध में अगणित अनुसंधानों के बावजूद आज भी निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी उत्पत्ति एवं विकास में कौन सी स्थितियाँ उत्तरदायी रही हैं। यद्यपि इसके विकास होने में सैंकड़ों वर्ष लग गये हैं समय-समय पर होने वाले परिवर्तन, विदेशी आक्रमण, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों तथा वर्ण-विरुद्ध-विवाह आदि अनेक तत्वों ने इसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। प्रस्तुत लेख के अंतर्गत विभिन्न जातियों की उत्पत्ति के संबंध में स्मृतिकारों के विचारों का उल्लेख किया गया है।

**21. "कुषाण-गुप्तयुगीन वैज्ञानिक प्रविधियों का समाजार्थिक प्रभाव"—पवन शेखर, नेट, जे.आर.एफ., इतिहास विभाग, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)**

मानव सर्जना के साथ ही जाने अनजाने में विज्ञान विकास और वर्तमान बौद्धिक एवं सांस्कृतिक स्तर तक के सफर का हमसफर रहा है। कुषाण-गुप्त युग में हुए तकनीकी विकास ने लोगों की कार्यपद्धति में बदलाव पैदा किया जिसके फलस्वरूप सामाजिक संरचना एवं आर्थिक स्थिति एक नवीन कलेवर के साथ उभरकर सामने आयी। इस युग में प्रचलित विज्ञान एवं तकनीकी ने समकालीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर चतुर्दिक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा जिसके फलस्वरूप भारत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से विश्व में अपनी छवि बना पाया। प्रस्तुत लेख कुषाण-युगीन वैज्ञानिक प्रविधियों के समाजार्थिक प्रभावों को उजागर करने का प्रयास कहा जा सकता है।

**22. "क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा की छात्राओं में महिला सशक्तीकरण का स्तर"**—अशोक प्रताप सिंह, बी.एड. प्रवक्ता, पाल कॉलेज ऑफ़ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वैसे तो पुरुष और महिला एक गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं, किन्तु सच्चाई यह है कि महिलाओं पर पुरुषों द्वारा शताब्दियों से अत्याचार हो रहे हैं। वैदिक काल में जहाँ स्त्री की पूजा होती थी, वहीं उत्तर-वैदिककाल के आते-आते नारी की स्थिति दयनीय होने लगी। मध्यकाल में तो स्त्रियों की स्थिति और भी खराब हो गई। इसी क्रम में आधुनिक कहे जाने वाले इस समाज में भी स्त्रियों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। शिक्षा जिसे व्यक्ति की सर्वांगीण विकास की आधारशिला माना जाता है, वह भी स्त्रियों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं कर पाई है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्राओं के मध्य महिला सशक्तीकरण के राजनीतिक जागरूकता आयाम व कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता सम्बन्धी आयाम के सन्दर्भ में प्रस्तुत तुलनात्मक अध्ययन सम्पन्न किया है।

**23. "समाज में स्त्रियों की स्थिति और महिला सशक्तीकरण के प्रयास"**—डॉ. प्रतिभा चतुर्वेदी, असि. प्रोफेसर समाजशास्त्र, यदुनाथ डिग्री कॉलेज, भिण्ड (म.प्र.)

सृष्टि के निर्माण एवं विकास में स्त्री और पुरुष दोनों का समान योगदान रहा है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों के सहयोग पर ही सृष्टि की निरंतरता टिकी हुई है। किन्तु समाज में नारी की स्थिति पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि नारी का स्थान न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में पुरुष की तुलना में निम्न रहा है। प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत अतीत से लेकर सांप्रत भारतीय समाज तक नारी की परिवर्ती स्थिति तथा महिला सशक्तीकरण के लिए किये गये शासकीय प्रयासों विशेषतः मध्य प्रदेश का उल्लेख किया गया है।

**24. "प्राचीन सरयू घाटी एवं सरयू नदी का अपवाह तंत्र"**—अली अफरोज, शोध अध्येता, प्राचीन इतिहास, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ.प्र.)

नदियों को देवी मानने वाले हमारे देश में नदी संस्कृति का विशेष महत्व रहा है। अपवाह का अभिप्राय जलधाराओं, नदियों तथा जल के धरातलीय प्रवाह से लगाया जाता है। यह प्रदेश के भूगर्भिक इतिहास को स्पष्ट करने के साथ ही प्राकृतिक स्थलकृति को भी आकार प्रदान करता है। प्राचीन काल से प्रसिद्ध सरयू नदी की अनेक सहायक नदियां हैं। अतः सरयू घाटी की अपवाह प्रणाली मुख्यतः उस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों से संबंधित है। प्रस्तुत लेख सरयू घाटी एवं सरयू नदी के अपवाह तंत्र को आलोकित करने का प्रयास रहा है।

**25. "भील जनजाति : राजस्थान के संदर्भ में"**—मंजूलता नागरे, शोध अध्येत्री, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

भील भारत की तीसरी तथा मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। भील प्रमुखतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान में पाये जाते हैं। ये लोग आज भी बीहड़, जंगलों, मरुस्थलों, ऊँचे पर्वतों, पठारों और दुर्गम स्थानों पर रहते हैं और आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति से अछूते हैं। प्रस्तुत लेख राजस्थान के भीलों का समाजशास्त्रीय अध्ययन है।

**26. "वर्तमान समय में बालिका शिक्षा की स्थिति"**—स्मृति वर्मा, शोध अध्येत्री, शिक्षाशास्त्र, एस.एस.जे. कुमायूँ विश्वविद्यालय परिसर, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

एस.सी. दुबे, एम. एस. गोरे, ए.आर. देसाई, एम. जयराम आदि अनेकानेक समाजशास्त्रियों ने शिक्षा को सामाजिक पुनर्गठन और आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण साधन स्वीकार किया है। सांप्रतिक भारत में बालिका

शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है न केवल पुरुषों से समानता प्राप्त करने के लिए प्रत्युत राष्ट्र की समाजार्थिक प्रगति के लिए भी बालिका शिक्षा की महती भूमिका है। किन्तु बालिका शिक्षा के मार्ग में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अनेक बाधाएं एवं समस्याएं हैं। प्रस्तुत आलेख वर्तमान समय में भारतमें बालिका शिक्षा की स्थिति तथा इसकी समस्याओं को उजागर करने की दिशा में एक प्रयास कहा जा सकता है।

**27. "उत्तराखण्ड की महिलाओं में चिपको आन्दोलन का प्रभाव एवं महत्व"—डॉ० सोहनी सेमवाल, अंशकालिक प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग, गर्ग पी०जी० कॉलेज, लक्सर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)**

चिपको आन्दोलन संभवतः विश्व का पहला आन्दोलन है जो इतने कम समय में संपूर्ण विश्व में चर्चित हुआ एवं फैल गया। अस्सी के दशक में इस आन्दोलन ने जनसामान्य में वन संरक्षण और वृक्ष रक्षा के लिए एक नई चेतना को जागृत किया। चिपको पेड़ों से चिपककर अथवा लिपटकर उन्हें काटे जाने का विरोध करने की एक विधि है। प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखण्ड के जनपद चमोली की महिलाओं के जीवन में चिपको आन्दोलन के महत्व एवं प्रभाव के विश्लेषण पर आधारित है।

**28. "पातालकोट की भारिया जनजाति में स्त्रियों की भूमिका एवं स्थिति"—श्रीमती रितु मेहरा, सहायक प्रध्यापक, संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.), सोनिया नाग, शोध अध्येत्री बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)**

नारी शक्ति, राष्ट्र और समाज की ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व के विकास करने में सर्वोपरि मानी गयी है। भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। महिलाओं की स्थिति किसी भी समाज की प्रगति के निर्धारण का महत्वपूर्ण मापदंड है। महिलायें ही भविष्य की पीढ़ी की नींव का निर्माण करती हैं, सम्पूर्ण भारतीय समाज व संस्कृति वर्तमान में परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। स्वतंत्रता पश्चात् आदिवासी समुदायों में अभूतपूर्व परिवर्तन आ रहे हैं जिनसे इन समुदायों की महिलायें अछूती नहीं है। इसी संदर्भ में पातालकोट की भारिया जनजाति की महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। प्रस्तुत शोध मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड के पातालकोट क्षेत्र में किया गया है। पातालकोट का शाब्दिक अर्थ है— पाताल को घेरनेवाला किला या पर्वत तथा भारिया का अर्थ है —भार ढोनेवाले।

**29. "असहयोग आन्दोलन : बिहार के मानभूम के सन्दर्भ में"—साहिदुज्जामन खान, शोध अध्येता, इतिहास विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)**

हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के इतिहास में मानभूम की भूमिका अहम रही है। 1856 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के खिलाफ पूरे हिन्दुस्तान में असंतोष की लहर सैलाब बन गयी, हर कदम पर चुनौतियों का सामना करते हुए अंग्रेज बेहाल हो रहे थे, तब मानभूम महाराजा नीलमणि सिंह देव ने भी इस लड़ाई में अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया। प्रस्तुत आलेख आजादी की लड़ाई के दौरान असहयोग आन्दोलन में बिहार के मानभूम के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करने के प्रयास पर आधारित है।

**30. "ग्रामीण समाज में दलितों की स्थिति: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण"—अमित कुमार वर्मा, शोध अध्येता—समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)**

भारत जिसमें अनेक धर्म एवं जातीय समुदाय के लोग रहते हैं। जिनमें से हिन्दू धर्म के अन्तर्गत एक समुदाय अस्पृश्यों का है जिनकी स्थिति चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक हो अत्यन्त दयनीय एवं शोचनीय रही है। इनकी स्थिति सुधारने हेतु अनेकानेक संवैधानिक व्यवस्थाएं आरक्षण व्यवस्था तथा दलितोद्धार की अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं जिनके फलस्वरूप उनकी वर्तमान स्थिति में सुधार हो रहा है। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत सांप्रत भारत में दलितों की स्थिति का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

**31. "नैनीताल के साह समुदाय का उपजातिगत विभाजन : एक अध्ययन"—श्रीमती प्रेमा चौधरी, शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, कु0वि0, नैनीताल (उत्तराखण्ड)**

प्रस्तुत आलेख उत्तराखण्ड राज्य के कुमायूँ प्रखण्ड के नैनीताल जनपद के नगरीय क्षेत्रों में आवासित साह समुदाय में सामाजिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों एवं साँस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत साह समुदाय में विद्यमान उपजातीयगत विभाजन जो उनकी उत्पत्ति विषयक संदर्भों के साथ प्रकाशित करने का एक प्रयास है।

**32. "कृषि महिला श्रमिकों की सहभागिता एवं समस्याओं का विश्लेषण"—कमलेश भार्गव, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, समाज विज्ञान अध्ययन शाला, देवी. अ.वि.वि. इन्दौर (म.प्र.), कु. मिसर नरगावे, शोध अध्येत्री समाजशास्त्र, समाज विज्ञान अध्ययन शाला, देवी. अ.वि.वि. इन्दौर (म.प्र.)**

सामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में तथा अर्थव्यवस्था के प्रत्येक स्वरूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यदि कृषि के संदर्भ में उनकी भूमिका का मूल्यांकन किया जाय तो उनका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण ही दृष्टिगोचर होता है। किन्तु हमारे समाज की पुरुष प्रधान सोच के फलस्वरूप आर्थिक उत्पादन में उनके योगदान को सदैव से नकार कर कृषि को पुरुष प्रधान व्यवसाय कहा जाता है। यह गंभीर चिंता का बिन्दु है। इसी सोच के परिणामस्वरूप कृषि के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की स्थिति आज भी अनेकानेक समस्याओं से ग्रस्त है। प्रस्तुत लेख कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता की स्थिति तथा उन समस्याओं को उजागर करने का प्रयास है जिन्हें वे अनुभव कर रही हैं।

**33. "टेलीविजन कार्यक्रमों का बच्चों पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव"—सुश्री गीतांजली, शोध अध्येत्री गृह विज्ञान, एन.के.वी.एम. गर्ल्स पी.जी. कालेज, चंदौसी (उ.प्र.)**

टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रभाव बच्चों पर सकारात्मक पड़ेगा या नकारात्मक यह सब टेलीविजन कार्यक्रमों पर निर्भर करता है तथा अभिभावकों का यह कर्तव्य बनता है कि वह इसके सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की जानकारी अपने बच्चों को दें तथा स्वयं भी इस बात का ध्यान रखें कि उनका बच्चा टेलीविजन पर किस तरह के कार्यक्रमों को देख रहा है और समय निकालकर बच्चों के साथ टेलीविजन कार्यक्रम देखें व इन कार्यक्रमों से बच्चों में उत्पन्न जिज्ञासा को शान्त करने का कार्य करें। प्रस्तुत अध्ययन बच्चों पर टेलीविजन कार्यक्रमों के सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभावों के मूल्यांकन का प्रयास रहा है।

**34. "महिलाओं में मोबाइल/इन्टरनेट बैंकिंग प्रयोग की स्थिति"—कु0 अर्चना सक्सेना, शोध अध्येत्री अर्थशास्त्र विभाग, बरेली कालेज, बरेली (उ.प्र.)**

सांप्रत प्रगत तकनीकी युग में महिलाएं भी पुरुषों की भांति प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही हैं और दोनों ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस तकनीकी युग में मोबाइल फोन एवं इन्टरनेट भी अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह करने में पीछे नहीं हैं। प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया गया है कि बैंकिंग प्रक्रिया में मोबाइल एवं इन्टरनेट की भूमिका को समझने व उसका प्रयोग करने के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति क्या है।

**35. पुस्तक समीक्षा—पुस्तक—भारत की जातियाँ : उद्भव एवं विकास, लेखक : डॉ. एस.एल. सिंह देव निर्मोही, प्राचार्य, ए.बी. महाविद्यालय गुरुसहायगंज, कन्नौज (उ.प्र.), समीक्षक—प्रोफेसर ए.एल. श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (अवकाश), समाजशास्त्र विभाग, बी.एच.यू. वाराणसी, एवं डॉ. सुमन मिश्रा, अध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग, श्री अग्रसेन कन्या (पी.जी.) कालेज, वाराणसी (उ.प्र.)**

**36. पुस्तक समीक्षा— पुस्तक : "कम्युनैलिज्म एण्ड द एन्टेलीजेन्सिया इन बिहार 1870—1930 : शेपिंग कास्ट कम्युनिटी एण्ड नेशनहुड", लेखक—डॉ. हितेन्द्र कुमार पटेल, अध्यक्ष इतिहास विभाग, रवीन्द्र भारती**



विश्वविद्यालय कोलकाता (बंगाल), समीक्षक—डॉ. कृष्ण कुमार मंडल, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, ति.माँ. भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर (बिहार)

37. **पुस्तक समीक्षा**— पुस्तक : विमन इन हिस्टारिकल पर्सपेक्टिव, लेखक : डॉ. रविशंकर कुमार चौधरी, इतिहास विभाग, टी.एन.बी. कॉलेज, भागलपुर, समीक्षक—डॉ. अनुराधा प्रसाद, राजनीति विज्ञान विभाग, एस.एम. कालेज भागलपुर